

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3440

दिनांक 16.03.2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

विशेष बलों का सुदृढीकरण

+3440. श्री राजेन्द्र धेड़्या गावितः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री रवि किशनः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुब्रत पाठकः

श्री चंद्र शेखर साहूः

श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विशेष बलों अर्थात् स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट वालेंटियर फोर्स का उन्नयन और सुदृढीकरण करने के लिए विशेष अवसंरचना योजना शुरु की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक उक्त योजना के प्राप्त उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के तहत विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस योजना को तीन और साल के लिए विस्तार हेतु राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के अनुरोधों पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक की- गई - कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) शुरु में 03 वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए अनुमोदित की गई, जिसे दिनांक 31.03.2021 तक आगे

बढ़ा दिया गया है। इस योजना में 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ राज्यों के विशेष बलों (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी) के अपग्रेडेशन और सुदृढीकरण की परिकल्पना की गई है।

विशेष बलों (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी) के संबंध में 371 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए 10 राज्यों के प्रस्तावों और 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण हेतु 07 राज्यों की 620 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। राज्य-वार स्वीकृत धनराशि अनुलग्नक में दी गई है। यद्यपि स्कीम का कार्यान्वयन प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जाता है, तथापि राज्यों को अग्रिम रूप में 152.67 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है।

अनुलग्नक

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	विशेष बलों (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी) का अपग्रेडेशन	250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) का निर्माण	
		कुल स्वीकृत धनराशि	अनुमोदित एफपीएस की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	23.0000	25	62.5000
2.	बिहार	67.8756	28	67.8868
3.	छत्तीसगढ़	68.0000	63	157.5000
4.	झारखंड	101.0000	64	156.7005
5.	महाराष्ट्र	12.0000	20	50.0000
6.	ओडिशा	55.0000	25	62.4137
7.	तेलंगाना	24.9343	25	62.5000
8.	मध्य प्रदेश	4.7300	-	-
9.	केरल	6.0000	-	-
10.	उत्तर प्रदेश	8.9996	-	-
	कुल	371.5395	250	619.5010
